



## II. विदेश व्यापार

5. विदेश व्यापार से संबंधित सभी विषय जिनमें व्यापार बातें और कारार (जिनमें ईरिक और व्यापार विषयक साधारण कारार और राष्ट्रमंडल ईरिक प्रधिनियम सम्मिलित है), व्यापार विषय और प्रतिनिधिमंडल, व्यापार महायोग और नवधन, और विदेशी भारतीय व्यापारियों के हितों को सरकार मिलित है।
6. आयात और नियात व्यापार नीति और नियंत्रण जिसमें निम्न-सिद्धित विषय सम्मिलित नहीं है :—
  - (i) काया चिन्हों का आयात;
  - (ii) भारतीय फिल्मों का नियंत्रण—दीर्घ और लंबु काया चिन्ह दोनों; और
  - (iii) चलचित्र (अनुद्भासित) और फिल्म उद्योग द्वारा प्रोत्साहित व्यवस्थाओं का आयात और वितरण।
7. मुख्य नियंत्रक, आयात और नियात।

## III. राज्य व्यापार

8. राज्य व्यापार की नीतियां और इस प्रयोजन के लिये स्थापित संगठनों का कार्य, जिनमें ये आते हैं :—
  - (i) राज्य व्यापार निगम और उसकी निम्नलिखित महायोग संस्थाएँ ;—
    - (क) भारतीय कानून निगम;
    - (ख) भारतीय परियोजना और उपस्कर निगम।
  - (ii) अनिज और धारु व्यापार निगम।

## गान्धी के साथ व्यापार, गान्धी सम्पत्ति

9. गान्धी के साथ व्यापार, गान्धी कर्म और गान्धी सम्पत्ति; हानि-पूर्ति (जर्मत औद्योगिक उपस्कर में विनाश), गान्धी-व्यापार नियंत्रक, गान्धी कर्म नियंत्रक; भारत के लिये गान्धी सम्पत्ति-प्रभिन्नक।
10. ईरिक आयोग [ईरिक आयोग प्रधिनियम, 1951 (1951 का 50)] उद्योगों को ईरिक संरक्षण, अन्तर्राष्ट्रीय सीमा-शुल्क ईरिक-व्यूगों।
11. सभी वस्तुओं, उत्पादों, प्रिनियाणों और प्रधर्ण निम्नियां, जिनमें निम्न-लिखित सम्मिलित हैं, से संबंधित नियात उत्पादन का विकास और विस्तार :—
  - (क) कृषि उत्पाद (शेषीकरण और अंकन) प्रधिनियम, 1937 के अन्तर्गत आने वाली कृषि उपज;
  - (ख) समूद्री उत्पाद;
  - (ग) औद्योगिक उत्पाद (इंजीनियरी का सामान, कैमिकल्स, प्लास्टिक, चमड़ा उत्पाद, आदि);
  - (घ) ईंधन, अनिज और अनिज उत्पाद;
  - (ङ) विनिर्दिष्ट नियातोन्मुख उत्पाद (जिनमें बांगान उपज आदि तो आते हैं जैसे किन पट्टन अत्याव और हस्तशिल्प नहीं आते) जो प्रत्यक्षतः इस विभाग के भारसाधन में हैं;
  - (च) वस्त्र, उनी वस्त्र, हथकरघा वस्त्र, रेखाएँ और सेलुलोसी तन्तु, पट्टन और पट्टन उत्पाद, और हस्तशिल्प।
12. वे सभी संगठन और संस्थाएँ जो निर्वाचित उद्यम से संबंधित सेवाओं की व्यवस्था से सम्बद्ध हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—
  - (क) नियात साज और प्रसामूहि निगम।
  - (ख) नियात निरीक्षण परिषदः।
  - (ग) वाणिज्यक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय।
  - (घ) प्रवर्गीय और वाणिज्य भारत निदेशालय
  - (इ) निःशुल्क व्यापार जोग।

13. नियात उद्यम के लिये प्रोत्साहक और सहायक परियोजनाएँ और कार्यक्रम।
14. आगात उपज, आय, काफी, रबड़, और इलायची का उत्पादन, वितरण (देश में उपल और नियात के लिये) और विकास।
15. (i) भारतीय चाय व्यापार निगम।
  - (ii) चाये बीई।
  - (iii) काकी बोई।
  - (iv) रबड़ बोई।
  - (v) इलायची बोई
  - (vi) हस्तशिल्प और हथकरघा-वस्त्र नियात निगम।

## ग नागरिक वृत्ति और सहकारिता विभाग

## I. आन्तरिक व्यापार

1. आन्तरिक व्यापार।
2. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, स्पर्ध-युक्त नियंत्रियां अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण प्रधिनियम, 1955।
3. व्यादा बाजार का नियंत्रण [प्रथम निवारण (विनियमन) प्रधिनियम, 1952]।
4. आवश्यक वस्तु प्रधिनियम, 1955 (ऐसी आवश्यक वस्तुओं का प्रयाप, कीमते और वितरण, जो विनिर्दिष्ट किसी अन्य मत्रालय द्वारा व्यवहृत नहीं है)।

## II. व्यापार विह आदि

5. व्यापार और वाणिज्य विह न प्रधिनियम, 1958।
6. संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) प्रधिनियम, 1950।
7. बाट और माप मानक (बाट और माप मानक प्रधिनियम, 1956—बाट और माप मानक प्रधिनियम, 1976)।
8. इस सूची में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी मल्हन या प्रधीनस्थ कायालय या अन्य संगठन, जिनमें फारबर्ड मार्केट्स कमीशन, बस्बर्ड भी सम्मिलित है।

## III. सहकारिता

9. सभी सेक्टरों में सहकारी और सहकारी नियाकलापों के समन्वय के क्षेत्र में साधारण नीति (संबंधित मकालय अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं के लिए उत्तरवायी है)।
10. राष्ट्रीय सहकारी संगठनों से संबंधित मामले।
11. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम।
12. ऐसी सहकारी सोसाइटियों का, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है, निगमन, विनियमन और परिसमाप्त।
13. सहकारी विभागों और सहकारी संस्थाओं के कामिकों का प्रशिक्षण (जिनमें सरस्थी, पदाधिकारियों और गैर-सरकारी व्यक्तियों की शिक्षा सम्मिलित है)।
14. उपभोक्ता सहकारी मस्थाएँ।
15. लोक विसरण प्रणाली।
16. कीमतों का परिवर्कण और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता।
17. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्।
18. पैक की दुई वस्तुओं का विनियमन।
19. कानूनी माप-विद्या में प्रशिक्षण।
20. भारतीय मानक मस्था (प्रमाणन विह न) प्रधिनियम, 1952।
21. वे उद्योग, जिनके लिए संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण सोकहित में समीक्षीय है, जहां तक

वे बनस्पति धी, तिलहन, बनस्पति तेलों, खाली और बमा से सम्बद्ध हैं।

22. बनस्पति धी, तिलहन, बनस्पति तेलों, खाली और बमा का अन्तर्राष्ट्रियक व्यापार और व्याणिज्य, उनका मूल्य-नियन्त्रण, पूर्ति और वितरण।

23. बनस्पति धी, बनस्पति तेल और बमा निदेशालय।”;

(ब) शोर्षक “पेट्रोलियम मंत्रालय”, और उसके प्रत्यंगत आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टिया रखी जाएंगी, अर्थात्—

“पेट्रोलियम, रमायन और उर्वरक मंत्रालय”

#### क. पेट्रोलियम विभाग

1. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन, प्रदाय, वितरण और कीमतें।

2. भारत में तेल के माध्यनों के लिए खोज और उनका शोषण, जिसके प्रत्यंगत भागदाही परियोजनाओं, उदाहरणार्थ हॉर्ड-स्टैनवैक पेट्रोलियम प्रोजेक्ट, आयस इंडिया लिमिटेड आदि की स्थापना भी है।

3. भारत में तेल परिकरणियों की स्थापना।

4. निम्नलिखित द्वारा परिकरणी उत्पादों का उत्पादन—

- स्टेन्डर्ड बैंकुअम रिफाइनरी कम्पनी, बम्बई;
- बम्गोल रिफाइनरी, बम्बई;
- कालटेक्स रिफाइनरी, विश्वापत्तनम; तथा
- असम आश्रम कम्पनी लिमिटेड, दिग्बोरी।

5. स्नेहक तेल संयंत्रों की स्थापना।

6. पेट्रो-रसायन।

7. सेलुलोसरहित संशिल्प फाइबर (नायनान, टेमीलीन, पोलियूस्टर, प्रिलिक आदि के उत्पादन से संबंधित उत्पादन।

8. संशिल्प रबड़।

9. प्लास्टिक, जिसमें प्लास्टिकों की विरचना और प्लास्टिक की डस्टी हुई वस्तुएं शामिल हैं।

10. पेट्रोलियम और पेट्रोलियम-उत्पादों के वित्रय के लिए वितरक संगठन की स्थापना।

11. विभाग द्वारा अवहृत सब उत्पादों की योजना, विकास तथा नियंत्रण और महायता।

12. इस सूची में विनियिष्ट विषयों में से किसी से संबंधित सभी संलग्न या अधीनस्थ कायानिय या अन्य संगठन, ऐसी परियोजनाओं के मिशन, जो किसी अन्य विभाग को विनियिष्ट प्रारंभित हैं, इस सूची में सम्मिलित किए गए विषयों के प्रत्यंगत आने वाली प्रब्लेम सेस्टर परियोजनाएं।;

#### द. रसायन और उर्वरक विभाग

1. उर्वरक।

2. औषधियों तथा प्रन्य सूधम रमायन।

3. कार्सिक सोडा और सोडा ऐश।

4. क्लोरीन।

5. सल्फ्यूरिक एसिड।

6. कीटनाशी (कीटनाशी प्रधिनियम, 1968 के प्रणालन के प्रतिरक्षित)।

7. ऐटिक्यूटिक्स।

8. पावल ऐल्कोहोल।

9. पेय ऐल्कोहोल।

10. ऊषा उपचार यवण।

11. रंजक द्रव्य।

12. कार्बनिक और अकार्बनिक भारी रसायन।

13. प्रकीर्ण रमायन, प्रयोति वे रमायन जो किसी अन्य विभाग को विनियिष्टतया प्रारंभित नहीं किए गए हैं।

14. विभाग से संबंधित सभी उत्पादों का आयोजन, विकास और नियन्त्रण तथा उन्हें सहायता।

15. इस सूची में विनियिष्ट किसी भी विषय से संबंधित सभी संस्थान अधीनस्थ कायानिय अपवा अन्य संगठन।

16. पायराइट्स, फासफेट्स एंड केमिकल्स लिंग।

17. इस सूची में सम्मिलित विषयों के प्रत्यंगत आने वाली प्रन्य सरकारी थेट्र की परियोजनाएं, जिनमें वे परियोजनाएं नहीं हैं जो किसी अन्य विभाग को विनियिष्टतया प्रारंभित की गई हैं।

नीलम मंजीव रेड्डी, राष्ट्रपति

[सं० 74/2/1/78-सौ० एफ०]

बादल राय, संयुक्त मण्डल

#### CABINET SECRETARIAT

##### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 1978

**S.O. 88(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

- (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) (One hundred and twenty-fifth Amendment) Rules, 1978.
- (2) They shall come into force at once.
2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961 (hereinafter referred to as the said rules), in the First Schedule,—
  - for entries 1A, 1B and 1C the following entry shall be substituted, namely:—
    - 1A. Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Vanijya, Nagrik Poorti aur Sahkarita Mantralaya):
    - (i) Department of Commerce (Vanijya Vibhag).
    - (ii) Department of Civil Supplies and Cooperation (Nagrik Poorti aur Sahkarita Vibhag).;
  - for entry 15, the following entry shall be substituted, namely:—
    15. Ministry of Petroleum, Chemicals and Fertilizers (Petroleum, Rasayan aur Urvarak Mantralaya):
    - (i) Department of Petroleum (Petroleum Vibhag).
    - (ii) Department of Chemicals and Fertilizers (Rasayan aur Urvarak Vibhag).;
3. In the Second Schedule to the said rules,—
  - the heading “MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA)”, and the entries thereunder shall be omitted;
  - the heading “MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRALAYA)”, and the entries thereunder shall be omitted;
  - for the heading “MINISTRY OF COMMERCE (VANIJYA MANTRALAYA)”, and the entries

thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

"MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (VANIJYA, NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA MANTRAI AYTA)".

**A. DEPARTMENT OF COMMERCE (VANIJYA VIBHAG)**

**I. General International Trade Policy**

1. International Commercial Policy.
2. International agencies principally connected with commercial policy (e.g. UNCTAD, ECAFE, ECA, ECIA, EEC, EFTA, GATT).
3. International commodity Agreements other than agreements relating to Wheat.
4. All matters relating to international trade policy including tariff and non-tariff barriers.

**II. Foreign Trade**

5. All matters relating to foreign trade including trade negotiations, and agreements (including General Agreements on Tariffs and Trade and Commonwealth Tariff Preferences), trade missions and delegations, trade cooperation and promotion, and protection of interests of Indian traders abroad.

6. Import and Export Trade Policy and Control excluding the matters relating to—

- (i) import of feature films;
- (ii) export of Indian films—both feature length and shorts; and
- (iii) import and distribution of cine-film (un-exposed) and other goods required by the film industry.

7. Chief Controller of Imports and Exports.

**III. State Trading**

8. Policies of State Trading and performance of organisations established for the purpose, including :

- (i) State Trading Corporation and its following subsidiaries :—
  - (a) Cashew Corporation of India;
  - (b) Projects & Equipment Corporation of India.
- (ii) Minerals & Metals Trading Corporation.

**IV. Trading with the enemy, enemy property**

9. Trading with the enemy, enemy firms and enemy property ; reparations (other than German industrial equipment); Controller of Enemy Trading ; Controller of Enemy firms ; Custodian of Enemy Property for India.

10. Tariff Commission [The Tariff Commission Act, 1951 (50 of 1951)], Tariff Protection to Industries, International Customs Tariff Bureau.

11. Development and expansion of export production in relation to all commodities, products, manufactures, and semi-manufacturers including the following :

- (a) agricultural produce within the meaning of the Agricultural produce (Grading and Marking) Act, 1937;
- (b) marine products;
- (c) industrial products (engineering goods, chemicals, plastics, leather products, etc.);
- (d) fuels, minerals and mineral products;
- (e) specific export-oriented products (including plantation crops etc. but excluding jute products and handicrafts) which are directly the charge of this Department.
- (f) textiles, woollens, handlooms, readymade garments, silk and cellulosic fibres, jute and jute products, and handicrafts.

12. All organisations and institutions connected with the provision of services relating to the export effort including :

- (a) Export Credit and Guarantee Corporation.
- (b) Export Inspection Council.
- (c) Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics.
- (d) Directorate of Exhibitions and Commercial Publicity.
- (e) Free Trade-Zones.

13. Projects and Programmes for stimulating and assisting the export efforts.

14. Production, distribution (for domestic consumption and exports) and development of plantation crops, tea, coffee, rubber and Cardamom.

15. (i) Tea Trading Corporation of India.

- (ii) Tea Board
- (iii) Coffee Board.
- (iv) Rubber Board.
- (v) Cardamom Board.
- (vi) Handicrafts and Handlooms Export Corporation.

**B. DEPARTMENT OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION (NAGRIK POORTI AUR SAHKARITA VIBHAG)**

**I. Internal Trade**

1. Internal Trade.

2. Inter-State Trade ; the Spirituous Preparations (Inter-State Trade and Commerce) Control Act, 1955.

3. Control of futures trading [The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952].

4. The Essential Commodities Act, 1955 (Supply, prices and distribution of essential commodities not dealt with specifically by any other Ministry).

**II. Trade Marks etc.**

5. The Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

6. The Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

7. Standards of Weights and Measures (The Standards of Weights and Measures Act, 1956—The Standards of Weights and Measures Act, 1976).

8. All attached or subordinate offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, including the Forward Markets Commission, Bombay.

**III. Co-operation**

9. General policy in the field of Co-operation and co-ordination of co-operation activities in all sectors (The Ministries concerned are responsible for Co-operatives in their respective fields).

10. Matters relating to National Co-operative Organisations.

11. National Co-operative Development Corporation.

12. Incorporation, regulation and winding up of co-operative societies with objects not confined to one State.

13. Training of personnel of co-operative departments and co-operative institutions (including education of members, office bearers and non-officials).

14. Consumer Co-operatives.

15. Public Distribution System.

16. Monitoring of prices and availability of essential commodities.

17. The National Consumer Protection Council.

18. Regulation of packaged commodities.
19. Training in legal Metrology.
20. The Indian Standards Institution (Certification Marks) Act, 1952.

21. Industries, the control of which by the Union is declared by Parliament by law to be expedient in the public interest, as far as these relate to Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

22. Price control of and inter-state trade and commerce in and supply and distribution of Vanaspati, Oil seeds, Vegetable Oils, Cakes and Fats.

23. Directorate of Vanaspati, Vegetable Oils and Fats.”;

(d) for the heading “MINISTRY OF PETROLEUM (PETROLEUM MANTRALAYA)”, and the entries thereunder, the following heading and entries shall be substituted, namely :—

“MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (PETROLEUM, RASAYAN AUR URVARAK MANTRALAYA).”

**A. DEPARTMENT OF PETROLEUM  
(PETROLEUM VIBHAG)**

1. Production, supply, distribution and prices of petroleum and petroleum products.
2. Exploration for and exploitation of oil resources in India including the setting up of participatory projects e.g. Indo-Stanvac Petroleum Project, Oil India Ltd., etc.
3. Setting up of Oil Refineries in India.
4. Production of refinery products by—
  - (i) Standard Vacuum Refinery Company, Bombay ;
  - (ii) Burmah-Shell Refinery, Bombay ;
  - (iii) Caltex Refinery, Visakhapatnam, and
  - (iv) Assam Oil Company Ltd., Digboi.
5. Setting up of lubricating oil plants.
6. Petrochemicals.
7. Industries relating to the production of Non-Cellulosic Synthetic Fibres (Nylon, Terylene, Polyester, Acrylic, etc.).
8. Synthetic Rubber.
9. Plastics, including fabrication of plastics and plastic moulded goods.

10. Setting up of a distribution organisation for the sale of petroleum and petroleum products.

11. Planning, development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.

12. All attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list, Public sector projects falling under the subjects included in this list except such projects as are specifically allotted to any other Department ;

**B. DEPARTMENT OF CHEMICALS AND FERTILIZERS  
(RASAYAN AUR URVARAK VIBHAG)**

1. Fertilizers.
2. Drugs and other fine chemicals.
3. Caustic Soda and Soda Ash.
4. Chlorine.
5. Sulphuric Acid.
6. Insecticides (excluding the administration of the Insecticides Act, 1968).
7. Antibiotics.
8. Power Alcohol.
9. Potable Alcohol.
10. Heat Treatment Salts.
11. Dye-stuffs.
12. Organic and Inorganic Heavy Chemicals.
13. Miscellaneous Chemicals i.e. Chemicals not specifically allocated to any other Department.
14. Planning, Development and control of, and assistance to, all industries dealt with by the Department.
15. All Attached or Subordinate Offices or other organisations concerned with any of the subjects specified in this list.
16. Pyrites, Phosphates and Chemicals Ltd.
17. Other Public Sector Projects falling under the subjects included in this list, except such projects as are specifically allotted to any other Department.”.

**N. SANJIVA REDDY, President**

[No. 74/2/1/78-CF]

**B. ROY, Jt. Secy.**

